

बिहार मानवाधिकार आयोग के कुछ पहल

- * डाक/फैक्स/e-mail पर प्राप्त परिवाद पत्रों का निःशुल्क पंजीकरण और उन पर अग्रत्तर कार्रवाई।
- * मामलों के त्वरित संज्ञान के कारण प्राप्त परिवाद पत्रों की संख्या में वर्षवार उत्तरोत्तर वृद्धि। (परिशिष्ट क)
- * आयोग के पहल पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में
 - (क) उप सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों की नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति।
 - (ख) जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय में एक ADM/ वरीय दंडाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति के पदाधिकारी की नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति।
- * मानवाधिकार संरक्षण हेतु और मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए आयोग द्वारा वृहद् पैमाने पर राज्य में sensitization कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- * आयोग कार्यालय में दिनांक 13.07.2012 को बिहार के सभी जोनल आई जी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों का sensitization work shop आयोजित किया गया।
- * राज्य के पांच प्रमंडलीय मुख्यालयों में प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रमंडल के जिलों के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों तथा NGO's के साथ sensitization work shop का आयोजन।

पूर्णिमा प्रमंडल	दिनांक	22.12.2012
मुंगेर प्रमंडल	दिनांक	12.01.2013
तिरहुत प्रमंडल	दिनांक	02.03.2013
दरभंगा प्रमंडल	दिनांक	23.04.2013
सारण प्रमंडल	दिनांक	29.06.2013

शेष प्रमंडलों में भी sensitization work shop प्रस्तावित है।

- * जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों को जिला स्तर पर नियमित अंतराल पर sensitization work shops आयोजित करने हेतु उत्प्रेरित किया गया है।
- * विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों यथा Law Unversities, विश्वविद्यालयों इत्यादि के विद्यार्थियों का आयोग में Internship कराया जाना। विगत वर्षों में आयोग में 204 विद्यार्थी Internship किये हैं। वर्तमान में 44 विद्यार्थी Internship कर रहे हैं। 40 विद्यार्थियों का अगला बैच 3 जनवरी 2014 से Internship करेगा।
- * आयोग के पदाधिकारियों का राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न Training Programme, Conferences, Seminars इत्यादि में भाग लेना।
- * दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को United Nations Day के अवसर पर आयोग में संगोष्ठी का आयोजन। दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को DPS, Patna के ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों के साथ interaction। इन छात्रों ने मानवाधिकार को विषय के रूप में लिया है।
- * मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित श्रेष्ठ नारों (Slogans) का चयन कर सरकारी विज्ञापनों में उनका नियमित प्रकाशन हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजा जाना प्रस्तावित है।

- * मानवाधिकार संरक्षण कार्यो से जुड़े गैर सरकारी संस्थानों (NGO's) को आयोग द्वारा प्रोत्साहित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है।
- * राज्य के District Disability Rehabilitation Centres (DDRC's) के पुर्नउत्थान और उन्हें प्रभावकारी बनाने हेतु आयोग द्वारा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ आवश्यक पहल की गयी है।
- * आबादी का लगभग 8% वृद्ध व्यक्तियों की आबादी है। उनके कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि से संबंधित विषयों पर आयोग ने भी पहल की है और सरकार द्वारा कई उल्लेखनीय/प्रशंसनीय कदम उठाए गए।

APPENDIX - A

Year wise Complaints received and disposed at BHRC.

Year	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
New Complainants Received	102	2727	3701	3831	4345	4782	19488
Total Disposal in the Year	88	1898	1246	620	2954	3452	10258

Subject wise breakup of complaints received in BHRC so-far.

No.	Types of Cases	2008-2013
1	Children	43
2	Education	308
3	Health	184
4	Jail	953
5	Judiciary	80
6	Mafias	1954
7	Labour	85
8	Minorities SC/ST	272
9	Police/Forces	6912
10	Pollution/Environment	69
11	Poverty Alleviation	343
12	Religion Community	31
13	Remand Homes	1
14	Service Matters	3099
15	Women	1135
16	Miscellaneous	4019
	Grand Total	19488